



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2012/आषाढ़ 6, 1934

No. 150]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2012/ASADHA 6, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2012

विषय : चीन जन.गण. से सोडियम परक्लोरेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच शुरू करना ।

फा.सं. 14/10/2012-डीजीएडी.—मै. कैलिबर केमिकल्स प्रा.लि. (एतदपश्चात “याचिकाकर्ता कम्पनी” अथवा आवेदक के रूप में संदर्भित) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (एतदपश्चात “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का अभिनिर्धारण, आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात “पाटनरोधी नियम” कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (एतदपश्चात “प्राधिकारी” के रूप में उल्लिखित) के समक्ष एक याचिका दायर कर, चीन जन.गण. (एतदपश्चात “संबद्ध देश” के रूप में भी उल्लिखित) में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित सोडियम परक्लोरेट (एतदपश्चात “संबद्ध वस्तु” के रूप में उल्लिखित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. से “सोडियम परक्लोरेट” है । सोडियम परक्लोरेट का उपयोग मुख्यतः खनन हेतु विस्फोटकों के विनिर्माण, परक्लोरिक एसिड तथा अन्य परक्लोरेटों के विनिर्माण तथा इंजीनियरी प्लस्टिक्स हेतु यूवी स्टेबिलाइजर के विनिर्माण में किया जाता है । सोडियम परक्लोरेट एक कार्बनिक यौगिक है तथा इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 (8 अंकीय परक्लोरेटों तक, उप-शीर्ष 28299010) के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

घरेलू उद्योग एवं स्थिति

3. यह याचिका मै0 कैलिबर केमिकल्स प्रा.लि. द्वारा दायर की गई है जो विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता है। अतः नियम के आशय से यह याचिका मानदण्डों को पूरा करती है और तदनुसार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का भाग है। याचिकाकर्ता ने इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि नियम 2 (ख) के आशय के अनुसार याचिकाकर्ता अथवा उससे संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।

समान वस्तुएँ

4 आवेदक ने दावा किया है कि विषयगत वस्तुएँ, जिनका निर्यात कथित देश द्वारा भारत को किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान उत्पाद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित सोडियम परक्लोरेट वस्तुओं के वास्तविक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद गुणों के रूप में तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों का उपयोग प्रतिस्थापनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक तौर पर प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए।

इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में माना जाता है।

शामिल देश

5 वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

सामान्य मूल्य

6 आवेदक ने बताया है कि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने विधिवत रूप से समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा यह कहते हुए किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था में लागत एवं कीमत पर विचार करने के लिए तीसरा देश उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ विचार किया गया।

निर्यात कीमत

7 भारत में आयात की मात्रा एवं मूल्य की गणना करने के लिए द्वितीयक स्रोत अर्थात् बालाजी डाटा इन्फोरमेशन सर्विसेज के आँकड़ों के आधार पर आवेदक ने निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए पत्तन प्रभारों, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री प्रभार, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन एवं वेट से संबंधित कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

8 आवेदक ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जो प्रथमदृष्टया पाटनरोधी जांच शुरू करने को सही साबित करने के लिए यह इंगित करते हैं कि संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन हो रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबध

9 आवेदक ने दावा किया है कि उन्हें घाटे, सामान सूची में वृद्धि, लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट और नकद लाभ, और अपने प्रचालन निष्पादन में आई गिरावट के कारण वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा है। आवेदक ने कीमत ह्रास, कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री के साक्ष्य के रूप में विपरीत कीमत प्रभाव का भी दावा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी विचार करते हैं कि पाटनरोधी जांच शुरू करने को सही ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई "क्षति" के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जाँच अवधि

10 वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक है। तथापि क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 08 - मार्च 09, अप्रैल 09 - मार्च 10, अप्रैल 10 - मार्च 11 और जाँच की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

11 संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में इस जाँच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं० 240
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107

समय सीमा

12 इस जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

13 सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटनरोधी नियम के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना हेतु पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया

जाएगा। गोपनीय सूचना के अगोपनीय रूपांतर या अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरा होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना का अर्थ समुचित रूप से स्पष्ट हो सके। यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विचार से ऐसी सूचना का सार तैयार करना संभव नहीं है तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में शामिल किसी भी तथ्य के बावजूद यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसका प्रकटन नहीं चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14 नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

15 ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2012

Subject : Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Sodium Perchlorate from China PR.

F. No. 14/10/2012-DGAD.—M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as 'petitioner company' or applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as 'AD Rules') for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Sodium Perchlorate (hereinafter also referred to as the 'subject goods') originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the 'subject country').

Product under consideration

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Perchlorate" from China PR. The main function of sodium perchlorate is to manufacture explosives for mining, in perchloric acid and other perchlorates manufacture and UV Stabilizer for engineering plastics. Sodium perchlorate is an organic compound and is classified under Chapter 28 (within perchlorates with 8 digit

subhead 28299010) of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd., which is the sole manufacturer of the product under consideration. Petition therefore, satisfy the standing and petitioner constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party within the meaning of Rule 2(b).

Like Articles

4. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject country into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Sodium Perchlorate produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules.

Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Subject Country

5. The country involved in the present investigation are China PR.

Normal value

6. The Applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted; stating that consideration of cost or price in a market economy third country is not available. The Normal value claims by the applicant have been considered for the purposes of initiation.

Export Price

7. The applicant has claimed export prices on the basis data from secondary source, i.e., Balaji Data Information Services to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of port expenses, inland freight, ocean freight, marine insurance, bank commission & VAT to arrive at the net export price.

2332 GT/12-2

Dumping Margin

8. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

Injury and Causal Link

9. The applicant has claimed that they have suffered material injury by way of losses, increase in inventories, decline in return on capital employed and cash profits, and deterioration in their operating performance. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression, price undercutting and price underselling. The applicant has claimed that the material injury has been caused due to the dumped imports from the subject country. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st April 2011 to 31st March 2012. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the period of investigation has been considered.

Submission of information

11. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.**

Time limit

12. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

13. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

14. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

15. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority